

2-07-2020

Dr. Purnima Singh
 Department of Political Science
 B.A part - II paper - III Indian
 Government and politics. Lecture - 59
 Topic - Federalism - 5

Federalism - 5

संघ और राज्यों में सम्बन्ध (Relation between centre and states)

1. वैधानिक सम्बन्ध (Legislative Relations)
 संविधान के भाग 11 (part XI) में अनुच्छेद 245-255 के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में वैधानिक सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 246 में तीन सूचियों की गई हैं -

- (1) संघीय सूची (Union List)
- (2) राज्य सूची (State List)
- (3) समवर्ती सूची (Concurrent List)
- (4) अवशिष्ट विषय (Residuary subjects)

(1) संघीय सूची (Union List) - संघीय सूची में 97 विषय हैं। इस सूची सूचि सूची में रक्षा, विदेशी कार्य, डाक - तार, रेलवे, टेलीफोन, सिन्के तथा राष्ट्रीय महत्व वाले विषय शामिल हैं। इस सूची में अंकित विषयों पर केवल संघीय संसद ही कानून बना सकती है,

(2) राज्य सूची (State List) - राज्य सूची में अंकित विषय 66 हैं। कृषि, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, लड़के पुलिस और जेल आदि के स्थानीय या प्रांतीय महत्व वाले विषय शामिल हैं। इस सूची में अंकित विषयों पर लाद्यायण विधायी में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।

राज्य सूची में अंकित विषयों पर केंद्रीय संसद को कानून बनाने की शक्ति (Power of Union Parliament to legislate on subjects in the State List) - विभाजित अवस्थाओं में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है -

4.

(क) राज्य सभा यदि दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची में अंकित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व वाला घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद एक वर्ष के लिए कानून बना सकती है, राज्य सभा एक और प्रस्ताव द्वारा इस अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2.

1.

(ख) जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा की जाए तो भी संसद को राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(ग) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में।

2.

(घ) राज्य विधानमंडल की कार्यवाही

(ड) अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List) - इस सूची में कुल 17 विषय दिए गए हैं। कौजकारी विधेय, न्यायिक प्रशासन, वन, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन आदि। इस सूची में अंकित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। परन्तु यदि किसी विषय पर बनाए गए कानून में गतिरोध पैदा हो जाता है तो केंद्रीय संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा।

3.

4.

4. अवशिष्ट विषय (Residuary Subjects) - संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत ऐसे विषय जिनका वर्णन उपरोक्त शक्ति तीन सूचियों में से किसी एक में भी नहीं किया गया उनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को है।
2. प्रशासनिक सम्बन्ध (Administrative Relation) संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के अन्तर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशासनिक सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है।
1. राज्यों द्वारा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार - संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य सरकारें अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस तरह करेंगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन होता रहे।
 2. अनुच्छेद 257 के द्वारा केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने के बारे में जरूरी निर्देश दे सकती हैं। इसी तरह संघीय के कानूनों के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय और लोकिक महत्व के भागी, पुलों, सड़कों आदि के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है।
 3. अनुच्छेद 258 के अनुसार किसी भी कार्य को केंद्र सरकार को और ही राष्ट्रपति राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी को लीज सकता है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
 4. अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें व्यापारों द्वारा दिए गए

